मनमोहन सरकार ने भ्रष्टाचार के विश्व कीर्तिमान बनाए हैं

केंद्र सरकार बनाम बाबा रामदेव

चिंतन

प्रभात कुमार रॉय

दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के हजारों सक्रिय समर्थकों के साथ जो सलूक दिल्ली पुलिस ने कर दिखाया, वह तो भारतीय लोकतंत्र की तवारीख में एक कलंक के तौर पर सदैव के लिए अंकित हो गया। बाबा रामदेव के विचारों और तौर-तरीकों से असहमत लोगों को भी पुलिसिया जुल्मोसितम से गहरा धक्का पंहुचा है। रात्रि 2 बजे सोते हुए लोगों पर वहशियाना ढंग से प्रहार किया गया और स्त्रियों और बच्चों को भी रामलीला मैदान से बुरी तरह से खदेड़ा गया। वाह री वाह काले अंग्रेजों की पुलिस, ऐसा व्यवहार तो गोरे अंग्रेजों की पुलिस ने भी शांतिपूर्ण अनशनकारियों के साथ कदाचित नहीं किया।

बाबा रामदेव ने अपने सक्रिय समर्थकों के साथ मिलकर मुल्क के उन तमाम लोगों बरखिलाफ ऐलान ए जंग किया है, जिन्होंने राष्ट्र के मेहनतकश जनमानस की अकूत संपदा को अवैध तौर पर लूटकर विदेश और देश में अपने कब्जे में इकट्ठा किया है। 1927 में शहीद ए आजम भगत सिंह ने अपने एक लेख में राष्ट्र के आवाम को यह स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यह मुमकिन है कि भारत साम्राज्यवादियों से आधी-अधूरी आजादी प्राप्त कर ले और गोरों के स्थान पर काले अंग्रेज भारतीय राजसत्ता पर काबिज हो जाए, किंतु इससे जनमानस को वास्तविक आजादी महसूस नहीं होगी। शहीद भगत सिंह का अंदेशा अक्षरशः सही साबित हुआ। आजादी हासिल हो जाने के ठीक बाद से ही काले अंग्रेजों द्वारा राष्ट्र की संपदा की ऐतिहासिक लूट प्रारंभ हो गई थी। पं. नेहरू काल में ही प्रख्यात अर्थशास्त्री सीडी देशमुख ने शासकीय भ्रष्टाचार के कारण निरंतर तीव्र गति से बढ़ते हुए काले धन के अपार सृजन पर चेताया था। सन् 60 के दशक में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सरीखे राष्ट्रीय नेता ने आम चुनाव में काले धन के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर अनेक तीखी चेतावनियां दीं। शासकीय भ्रष्टाचार और इसकी बदौलत काला धन के तौर पर अकूत दौलत सुरसा के मुख की तरह बढ़ती चली गई।

बाबा रामदेव ने विदेशों में जमा की गई काली संपदा के विरुद्ध देशभर में सशक्त अभियान छेड़ा। बाबा रामदेव समूचे काले धन को बाकायदा जब्त करके उसे राष्ट्रीय संपदा घोषित करने और बड़े नोटों की करेंसी को प्रचलन से बाहर करने की मांग करते रहे हैं। बाबा रामदेव के अभियान को भारतीय समाज के प्रायः सभी तबकों और वर्गों के करोड़ों लोगों की हिमायत हासिल हुई। काले धन के ज्वलंत प्रश्न पर साधारण जन गण की जबरदस्त हिमायत ही बाबा रामदेव की असल ताकत है, जिसके खौफ से केंद्रीय सत्ता शांत प्रदर्शनकारियों पर इस कदर हमलावर हो गई। आरएसएस के खुलकर बाबा रामदेव के समर्थन में आ जाने के पश्चात तो काले धन के विरुद्ध शुरू संग्राम में अजब संदेह का वातावरण सृजित हुआ। बाबा रामदेव ने आरएसएस से अपनी मुहिम को अलग भी नहीं किया। इससे एक पूर्णतः अराजनीतिक संग्राम बाकायदा राजनीतिक रंग रूप ले गया। सर्वविदित है कि आरएसएस दिखावे के लिए एक सामाजिक तंजीम है, किंतु इसका असल मकसद राजनीतिक तौर पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का पोलिटिकल चेहरा मोहरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब 1998 से 2004 तक सत्तानशीन रही तो उसे काले धन से निपटने का कतई खयाल नहीं आया। अब भारतीय जनता पार्टी की जननी आरएसएस बाबा रामदेव को मोहरा बना कर एक नया राजनीतिक पैंतरा चलने पर उतारू हो रही है।

जिस तरह से मनमोहन सिंह सरकार ने अन्ना हजारे को जन लोकपाल बिल के सवाल पर धोखा दिया है, उससे अन्ना हजारे बहुत अधिक आहत हुए हैं। जन लोकपाल बिल के दायरे से प्रधानमंत्री और सांसदों को बाहर रखने के लिए सरकार अड़ी हुई है। सरकारी रवैये के कारण एक महीने की कवायद के बाद भी जन लोकपाल बिल की आउट लाइन तक तैयार नहीं हो पाई। उसी तरह काले धन के सवाल पर एक कमेटी बनाकर मनमोहन सिंह हुकूमत बाबा रामदेव को टरकाने की कोशिश करती रही। बाबा रामदेव को रामलीला मैदान में धरना अनशन से विमुख करने के लिए केंद्रीय हुकूमत ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। बाबा रामदेव को केंद्रीय हुकूमत के वरिष्ठ मंत्रियों ने झांसे में लेकर एक समझौते पर उनके सचिव के दस्तखत भी ले लिए। जब बाबा रामदेव को सरकार की चालाकी समझ आई तो देर हो चुकी थी। क्योंकि यह वही हुकूमत है, जिसकी कयादत में शासकीय भ्रष्टाचार के विश्व रिकार्ड ध्वस्त हुए हैं।

भारतीय जनता पार्टी जब 1998 से 2004 तक सत्तानशीन रही तो उसे काले धन से निपटने का कतई खयाल नहीं आया

मनमोहन सिंह हुकूमत की निगरानी के तहत अनाज आयात घोटाला, शुगर स्कैम, 2 जी स्पैक्ट्रम स्कैंडल आदि अस्तित्व में आए। इस हुकूमत के जेरे साया काले धन के बड़े जखीरेबाज हसन अली के खिलाफ कोई कदम कदाचित नहीं उठाया गया। आखिरकार हसन अली के विरुद्ध अदालती हुक्म से ही कार्रवाही अंजाम दी गई। कैसा अद्भुत ईमानदार चरित्र रहा है मनमोहन सिंह सरकार का कि जिसने सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद विदेशी काले धन के जखीरेबाजों के बरखिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही अंजाम नहीं दी।

केंद्रीय हुकूमत तो महज कमेटियां गठित करती है। इन सरकारी कमेटियों की सिफारिशों पर कदाचित अमल दरामद नहीं होता। इन पंक्तियों का लेखक अनेक उच्च स्तरीय सरकारी कमेटियों का सदस्य रह चुका है और यह बात संजीदगी से बयान करता है कि यदि सरकार द्वारा गठित कमेटियों और कमीशनों की सिफारिशों पर शिद्दत के साथ अमल किया गया होता तो संभवतया राष्ट्र कुछ समस्याओं से तो निजात पा ही लेता। बाबा रामदेव को झांसे में लेने के लिए संभव है कि सरकार एक और कमेटी काले धन के लिए गठित कर डाले किंतु पहले काले धन पर गठित एक सरकारी कमेटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में कहा था कि प्रतिवर्ष तकरीबन 60 हजार करोड़ राशि काले धन के तौर पर विदेशों में ले जाई जाती है, इस विशाल धन राशि के विदेशों में जाने से प्रतिबंधित करने के कुछ उपायों की सिफारिश की गईं, जिन पर कभी कोई अमल नहीं किया गया।

दरअसल काले धन के प्रकोप को खत्म करने के लिए भारतीय राजनीति और राजनीतिक दलों के मूलभूत चरित्र को ही परिवर्तित करना होगा। जो राजनीति इस कदर भ्रष्ट हो चुकी हो कि उसके अधिकतर बड़े दलों का और उनके चुनावी शिरकत का संपूर्ण संचालन ही काले धन से हो रहा हो, भला उनसे कैसे कोई उम्मीद लगाता है कि वे अपने काले धन के जखीरेबाज आकाओं को खत्म कर देंगे? सर्वविदित रहा है कि चुनाव जीतने की खातिर बड़े राजनीतिक दल अरबों-खरबों रुपए खर्च करते रहे हैं। नारकोटिक ड्रग्स और हथियारों के तस्कर, खूंखार अपराधी राजनीतिक दलों की पनाहगाहों में विराजमान हैं। संसद और विधान सभाओं में कितने ही खतरनाक क्रिमिनल्स काली कमाई के दमखम पर बाकायदा सदस्य हैं।

मोबाइल:09319310533

Reproduced by www.hobbyshobby.com with author's permission